

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संदर्भ समिति के लिए प्रशिक्षण निर्देशिका





अनुक्रमणिका तथा सत्र अनुसार गतिविधियां

प्रस्तावना	1
संक्षेपाक्षर	2
प्रशिक्षण के उद्देश्य व अपेक्षाएँ	3
परिचय सत्र	4
बच्चे की परिभाषा	5
बाल अधिकार	6-17
ग्राम पंचायत स्तरीय बाल सुरक्षा समिति	18-21
मीटिंग व कोरम	22-23
बाल संरक्षण	24
बाल मैत्री गांव/पंचायत	25-26
सूत्रधार की भूमिका, समापन एवं धन्यवाद समारोह	27-28





प्रस्तावना

भारत की कुल जनसंख्या का 44 प्रतिशत बच्चे हैं तथा 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है अतः गांवों में रहने वाले बच्चों की जनसंख्या भी ज्यादा है इसलीये सरकार द्वारा गांव स्तर पर बच्चों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है। इस समिति के गठन करने का उद्देश्य ग्राम व ग्राम पंचायत स्तर पर बच्चों का संरक्षण, उनके संवर्गीण विकास, उचित देखभाल करने के लिए परिवारों का मार्गदर्शन व समर्थन, विभिन्न सरकारी योजनाओं को बच्चों के लिए प्रभावी बनाने तथा बाल मित्र ग्राम बनाना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति प्रशिक्षण निर्देशिका को तैयार किया गया है। हम आशा करते हैं कि यह पुस्तक ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को बच्चों के प्रति अपनी भूमिका निभाने में मदद करेगी।

हर बच्चे का यह अधिकार हैं की उसे सुरक्षा एवं गरिमा के साथ जीने के लिए, सुरक्षात्मक वातावरण मिले। बच्चों को विद्यालय में, सुमदाय तथा घर में हिंसा, उपेक्षा, शोषण एवं लिंग आधारित भेदभाव से संरक्षण मिलना चाहिए। बच्चे समुदाय और देश की परिसंपत्ति हैं। बच्चों को रुक्ष देने, उनकी देखभाल करने तथा उनके साथ सम्मान और मर्यादा का व्यवहार किये जाने की आवश्यकता है। जिस बच्चे की सही रूप से देखभाल और उसका सही पालन पोषण होगा वह बच्चा अवश्य ही देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा।





संदोपाक्षर

पी. अल. सी. पी. सी.	ग्राम पंचायत स्तररय बाल संरक्षण समिति
सी. बी. ओ.	समुदाय आधारित संस्था
सी. डब्ल्यू. सी.	बाल कल्याण समिति
जी. पी.	ग्राम पंचायत
टी.सी.पी.यू	जिला बाल संरक्षण इकाई
आई. सी. डी. एस.	समेकित बाल विकास सेवाएँ
आई सी. पी. एस.	समेकित बाल संरक्षण योजना
आई. ई. सी.	सूचना शिक्षा संचार
जे. जे. बी.	किशोर न्याय बोर्ड
एन. जी. ओ.	गैर-सरकारी संगठन
ओ. बी. सी.	अन्य पिछड़ा वर्ग
पी. एच. सी.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
पोक्सो	यौवन अपराध से बच्चों का संरक्षण कानून
एस. एच. जी.	स्वयं सहायता समूह
एस. जे. पी. यू.	विशेष किशोर पुलिस इकाई
एस. एम. सी.	विद्यालय प्रबंधन समिति
एस. एस. ए.	सर्व शिक्षा अभियान
यू. एन. सी. आर. सी	बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज



प्रशिक्षण के उद्देश्य :

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य समिति के सदस्यों को बाल संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए समिति में उनके अधिकारों, शक्तियों, व जिम्मेदारियों के प्रति अवगत करवाना तथा उनमें बाल संरक्षण के लिए कार्य करने की सौच विकसीत करते हुए :-

1. ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन की प्रक्रिया व कर्तव्य को समझना।
2. समिति एवं ग्राम वासियों द्वारा बच्चों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना एवं बाल संरक्षण कार्ययोजना बनाना तथा इसे लागू करना।
3. सभी सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
4. बाल संरक्षण से संबन्धित दस्तावेज तैयार करना एवं आगे पंचायत समिति व जिला स्तरीय बाल संरक्षण समिति या इकाई को भेजना।
5. बाल संरक्षण से संबन्धित विभागों एवं अधिकारीयों से समन्वय स्थापित करना।
6. सभी गांवों को बालमित्र बनाना।
7. ग्राम व ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं की सुचारू निगरानी रखना।
8. बच्चों से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा कर उनका निराकरण करना।

प्रशिक्षित प्रशिक्षकों से अपेक्षाये :

पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण की शुरुआत करने से पहले सभी प्रशिक्षक निम्नलिखित तैयारी सुनिश्चित कर ले :-

1. प्रशिक्षण से पांच दिन पूर्व सभी प्रतिभागियों को सूचित कर दें।
2. प्रशिक्षण पूर्व सभी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना व सुची बनाना।
3. प्रशिक्षण के दिन बताये समय से पहले पंहुचकर सभी तैयारीयों का जायजा लेना एवं सुनिश्चित करना कि सभी तैयारियां पुर्ण हो गई हैं।
4. सभी सदस्यों की जिम्मेदारी निर्धारित करना एवं उसे निभाना।

प्रशिक्षण के नियम :-

1. समय का ध्यान रखना।
2. प्रशिक्षण विधी का पुरा उपयोग करना एवं जरूरत के अनुसार उसमें अपने अनुभव जोड़ना।
3. प्रशिक्षण में किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
4. सभी को बोलने का एवं अपने विचारों को रखने का बराबर मौका मिले।
5. सहभागियों का आदर करना चाहिए। उन्हे एहसास कराएं कि वे विशिष्ट व्यक्ति हैं और उनकी पूरी देखभाल की जा रही है।
6. स्थानीय भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें।
7. सभी सत्रों के बाद पठन पाठन सामग्री उपलब्ध करवायें।
8. प्रशिक्षण को निर्देशिका के अनुसार ही रोचक तरिके से करवाया जाये।
9. प्रशिक्षण में स्थानीय जरूरतों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
10. स्थानीय तथा जिला अधिकारियों के दूरभाष नम्बर भी सदस्यों को उपलब्ध करवायें।



परिचय सत्र

समयावधि :- 30 मिनट

संदर्भ व्यक्ति सहभागियों का स्वागत करेंगे। पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी सदस्य अपना नाम, समिति में धारित पद, गाँव का नाम और अपने गाँव की कोई खास बात यदि बताना चाहें तो बताएंगे।

ताली द्वारा परिचय :- सभी सहभागी पहले ताली बजाकर अपना परिचय देंगे तथा उसके बाद अगल - बगल वाले साथी का नाम लेकर ताली बजायेंगे, बगल वाला साथी इसी क्रम में अगले साथी का ताली बजाकर नाम बोलेगा। इस प्रकार यह क्रम तब तक चलेगा जब तक सभी संभागी सहज न हो जाये।



सामुदायिक सहभागिता का महत्व

उद्देश्य :-

1. पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्य सामुदायिक सहभागिता का महत्व समझे।
2. पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्य समिति में स्वयं की भूमिका व महत्व को समझे।

आवश्यक सामग्री - पत्थर के टुकड़े, किताबें, अखबार, मार्कर, चार्ट, स्कैच पेन, सेलो टेप इत्यादि।

गतिविधि-1 पत्थरों की मीनार बनाना।

संदर्भ व्यक्ति संभागियों के 3 या 4 (आवश्यकतानुसार) समूह बनाएंगे। सभी समूहों के सदस्यों को अपना नेता चुनने को कहेंगे। समूहों के बीच 30-35 छोटे छोटे पत्थरों (किताब या अखबार भी ले सकते हैं।) को बिखरे देंगे। गतिविधि को तीन चरण में पूरा करना है।

प्रथम चरण :- समूह नेता अपने हाथ के इस्तेमाल द्वारा पत्थरों की मीनार बनाएंगा। बाकी सदस्य केवल देखेंगे। समय 1 मिनट होगा। इस दौरान संदर्भ व्यक्ति सभी समूह के नेता द्वारा किए कार्य को देखेंगे। मीनार को फिर बिखरे देंगे।

द्वितीय चरण :- संदर्भ व्यक्ति समूह को अपने नेता के सहयोग के लिए एक साथी चुनने को कहे। अब नेता और उसका साथी एक हाथ द्वारा पत्थरों की मीनार बनाएंगे। बाकी नेता द्वारा किए कार्य को देखेंगे। समय 1 मिनट होगा। इस दौरान संदर्भ व्यक्ति सभी समूह के नेता द्वारा किए कार्य को देखेंगे। मीनार को फिर बिखरे देंगे।

तृतीय चरण :- इस बार समूह के सभी सदस्य नेता को सहयोग करेंगे। सभी सदस्य अपने एक हाथ से 1 मिनट में पत्थरों की मीनार बनाएंगे। इस दौरान संदर्भ व्यक्ति सभी समूहों के द्वारा किए गये कार्य को देखेंगे।

तीनों चरणों के पूरा होने के पश्चात् संदर्भ व्यक्ति समूह के साथ निम्न सवालों पर चर्चा करेंगे-

1. तीनों चरणों में क्या हुआ ? नेता व सदस्यों से उनके अनुभव पूछें।
2. तीनों चरणों में से कौन से चरण में मीनार अच्छे से बन पाई और क्यों ?

समेकन :-

1. जिस प्रकार किसी भी कार्य को सफल सम्पादन के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है उसी प्रकार बच्चों के समेकित विकास के लिए प्रत्येक सदस्य की महत्वपूर्ण भूमिका व भागीदारी रहती है।



बच्चे की परिभाषा

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज जो कि बाल—अधिकारों पर तैयार एक अन्तर्राष्ट्रीय कानून मानक है जिस पर विश्व के 192 देशों ने हस्ताक्षर किये तथा उसको लागू किया है। इसके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के लड़का एवं लड़की बच्चे कहलाते हैं। अतः आपकी पंचायत क्षेत्र में आने वाले सभी बच्चों के संरक्षण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की है।

मुख्य विन्दु :

- 18 वर्ष से कम उम्र के लड़का अथवा लड़की बालक कहलाते हैं।
- बचपन एक ऐसा दौर है जिससे हर व्यक्ति गुजरता है।
- बचपन में बच्चे विभिन्न तरह के अनुभव करते हैं।
- अभद्र व्यव्हार एवं पोषण से सभी बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए।



बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता क्यों है ?

बच्चों को व्यस्कों की तुलना मैं ज्यादा खतरा रहता है।

चुकिं बच्चों के कोई आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक आदि अधिकार प्राप्त नहीं होते व बच्चे अपने अभिभावक पर निर्भर होते हैं व उनके निर्णय उनके अभिभावक ही लेते हैं। बच्चों को आसानी से बहलाया, फुसलाया जा सकता है तथा उनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चे अपने साथ होने वाले अपराध के खिलाफ आवाज भी नहीं उठ सकते इसलिये बच्चे समाज में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं जिसके कारण उनको विशेष देखभाल की ज़रूरत है।





बाल अधिकार

भारत का संविधान देश की सभी जातियों, समुदायों तथा धर्मों से सम्बंधित सभी बच्चों को, चाहे वे शहर में रहते हो या गाँवों में, समान रूप से मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें मुख्य रूप से ये अधिकार शामिल हैं।

1. जीवन जीने का अधिकार
2. संरक्षण का अधिकार
3. विकास का अधिकार
4. सहभागिता का अधिकार

इन मुख्य चार अधिकारों के अलावा बच्चों को निम्नलिखित अधिकार भी संविधान द्वारा प्रदत्त हैं:-

- 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का प्रावधान (अनुच्छेद 21 अ)
- 14 वर्ष की उम्र तक बच्चों को किसी भी प्रकार के जोखिम भरे रोजगार से बचाना (अनुच्छेद 24)
- बच्चों को उनकी आयु एवं शक्ति के अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश के लिए आर्थिक आवश्यकता से मजबूर करने से उनकी रक्षा करना (अनुच्छेद 39 ई)
- बच्चों को एक स्वस्थ, स्वतंत्रता एवं गरिमामय जीवन जिसमें शोषण से सुरक्षित बचपन एवं जवानी हो ऐसा वातावरण में उनका विकास होना चाहिये (अनुच्छेद 39 च)





जीवन जीने का अधिकार

भारत में निवास करने वाले हर बालक को समान रूप से जन्म लेने का, उचित देखरेख, पर्याप्त पोषण, उचित स्वास्थ्य एवं शिक्षा, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, पहचान, राष्ट्रीयता और नाम का अधिकार है।

गर्भधारण करने से लेकर जन्म तक बच्चे का स्वास्थ्य उसकी माता के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है और इस प्रकार शिशुओं का जन्म के बाद जीवित रहना उनके जन्म के पूर्व से लेकर दो वर्ष की आयु तक किये गए अनेक महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करता है। बच्चों के जीवित रहने के लिए गर्भावस्था के दौरान माता की देखभाल की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। माता और नवजात शिशु के लिए बेहतर देखरेख सुनिश्चित करने में परिवारों को जानकारी प्रदान करने तथा साथ ही ठीकाकरण के साथ बेहतर चिकित्सा देखरेख सुनिश्चित करने और ग्राम पंचायत इन मुद्दों के बारे में परिवारों को जानकारी प्रदान करने तथा साथ ही ठीकाकरण के साथ बेहतर चिकित्सा देखरेख सुनिश्चित करने और ग्राम पंचायत क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्था करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में बच्चों की उत्तरजीविता तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए अन्य मुख्य स्वास्थ्य संस्थाएँ जैसे ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (वी.एच.एस.एन.सी.), रोगी कल्याण समिति और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र पर आशा, ए.एन.एम. आदि के साथ समन्वय बनाते हुए कार्य करे, इन्हें सहयोग प्रदान करे तथा साथ ही इनके कार्यकरण की निगरानी भी करे।



I. गर्भावस्था, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण :

ए.एन.एम. उप स्वास्थ्य केंद्र / आंगनबाड़ी में ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस के दौरान गर्भवती महिला का पंजीकरण करती है तथा उसे माता एवं बाल संरक्षण कार्ड (एम.सी.पी.) प्रदान करती है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार भारत में जन्म, मृत्यु तथा मृत पैदा हुए बच्चों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत सचिव अथवा स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी को जन्म/मृत्यु के होने के 21 दिन के भीतर या उसके पश्चात शीघ्र ही जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करना चाहिए।

गर्भावस्था का पंजीकरण कन्या भूषण-हत्या पर नजर रखने के लिए उपयोगी है, जन्म का पंजीकरण बालिका हत्या तथा बाल विवाह पर नजर रखने में मदद करता है !

II. ठीकाकरण :

ठीकाकरण एक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के जीवन को संकट में डाल देने वाले रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ठीके की दवाई शरीर में रोगप्रतिकारकों अथवा ऐसे पदार्थों को उत्पन्न करने के योग्य बनाते हैं और इस प्रकार बच्चा बीमार होने से बच जाता है। समिति की यह जिम्मेदारी बनती है की वे ठीकाकरण को लेकर सम्बंधित विभाग एवं अधिकारियों को सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करे तथा समुदाय में इसके प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूकता प्रदान करे।

III. बच्चों के लिए सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और साफ-सफाई

विशेष रूप से 0-5 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों को अस्वस्थ परिस्थितियों के फलस्वरूप प्रभावित होने का खतरा सबसे अधिक होता है तथा वे असुरक्षित पेयजल से अधिक बीमार पड़ते हैं। पानी से पैदा होने वाली बीमारियों जैसे हैंजा और दस्त इस आयु वर्ग में बच्चों की मृत्यु का प्रमुख कारण है।

पानी को पिने के लिए तभी सुरक्षित माना जाता यदि वह रंगहीन, गंधहीन, जीवाणुओं के संदूषण से मुक्त हो तथा इसमें रसायन केवल निर्धारित सीमा तक ही हो। पानी अनेक कारणों से प्रदूषित होता है जैसे हवा में विधमान प्रदूषण-तत्व, भूमि में विधमान खनिज, मनुष्य और पशुओं का मल, मूत्र, कपड़े धोने से, उर्वरको, कीटनाशकों के प्रयोग से, घरों में गलत तरीके से पानी के रखरखाव तथा गंदे हाथों से साफ पानी की छुने से साफ पानी भी प्रदूषित हो जाता है !





साफ-सफाई का अर्थ है स्वास्थ्य को अच्छा बनाये रखने के लिए संचालित की जाने वाली प्रक्रियाये जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाश्मों को फैलने से रोकती है। इसमें व्यक्तिगत साफ-सफाई भी शामिल है जैसे नियमित रूप से नहाना, दांतों की देखभाल और हाथ धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनना।

स्वच्छता में शामिल है मनुष्य और पशुओं के मल का सुरक्षित निपटान, पेयजल का सुरक्षित भण्डारण और प्रयोग, व्यर्थ द्रव्य और ढोस अपशिष्ट का आदि का सुरक्षित निपटान।

ग्राम स्वच्छता पोषण दिवस के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम. और आशा समुदाय को वाश (जल, स्वच्छता और साफ-सफाई) संबंधी जानकारियां प्रदान कर सकती हैं स्वच्छ भारत अभियान की निधि का प्रयोग करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र में शोचालयों का निर्माण किया जा सकता है।



बच्चों के लिए बेहतर जीवन तथा विकास

जागरूकता
एवं उत्तरदायी
समाज

व्यवहार
में
परिवर्तन

जल
एवं
स्वच्छता

ग्राम पंचायत क्षेत्र में बच्चों का सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए पी.अल.सी.पी.सी. की भूमिका :

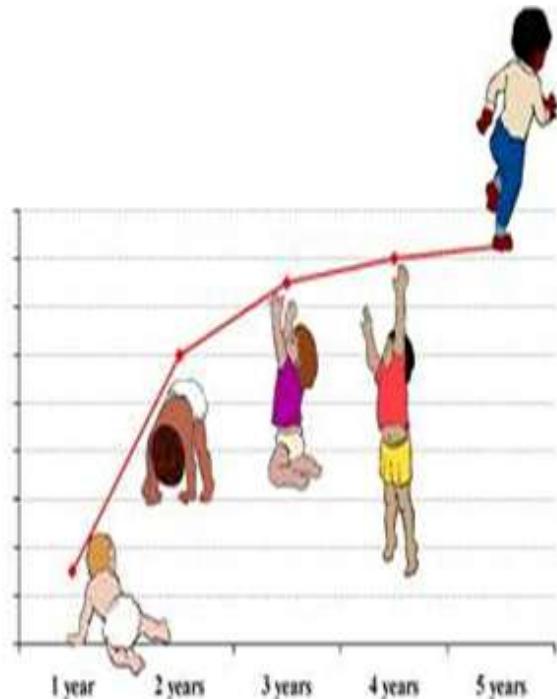


ग्राम पंचायत लोगों को गर्भधारण, जन्म / मृत्यु पंजीकरण तथा टीकाकरण चार्ट के अनुसार बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम का अनुपालन करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करते हुए ग्राम पंचायत क्षेत्र में बच्चों की मृत्यु - दर और अस्वस्थता - दर में कमी लाने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है। समिति विद्यालयों तथा आंगनबाड़ीयों में स्वच्छ पेयजल व् स्वच्छता को सुनिश्चित कर सकती है ग्राम पंचायत इन पहलुओं के संबंध में ग्राम सभा की बैठकों में, वार्ड सभा, महिला सभा, स्वयं सहायता समूह की बैठकों, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर तथा आंगनबाड़ीयों द्वारा आयोजित किशोर / किशोरी दिवसों पर लोगों के बीच जागरूकता और जानकारी का संचार कर सकती है। समिति को यह सुनिश्चित करना होगा की भोगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, प्रवासी लोगों आदि तक सूचना तथा सेवायें अवश्य पहुंचे।



विकास का अधिकार :

प्रत्येक बच्चे के लिए प्राथमिक स्तर तक की अनिवार्य गुणात्मक शिक्षा , खेल, आराम, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों की व्यवस्था, बाल्यावस्था में उचित देखरेख, माँ बाप का प्यार एवं पारिवारिक सहयोग, शारीरिक एवं मानसिक विकलांग बच्चों के लिए विशेष देखरेख, सांस्कृतिक व् सामाजिक विकास, मानवीय मूल्यों को बढ़ावा, स्वच्छ पर्यावरण तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण द्वारा व्यवहारिक ज्ञान व कला कौशल का विकास। प्रत्येक बच्चे के पास उत्प्रेरणा, शिक्षा, खेल-कूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक क्रिया-कलाओं के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक विकास का अधिकार है ताकि वह अपने व्यक्तित्व का विकास अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुरूप कर सके। जैसे-जैसे बच्चों की आयु बढ़ती जाती है, उनका विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से होता है, उनमें समझने और सीखने की क्षमता का विकास होने लगता है। हम बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जितना अधिक ध्यान देंगे उनका उतना ही अच्छा शारीरिक और मानसिक विकास होगा। आइए बच्चों के विकास के प्रमुख पहलुओं और उनमें समिति की भूमिका के बारे में जाने।



I. स्वास्थ्य और पोषण

पोषण का अर्थ है ऐसा आहार जिससे शरीर की भोजन संबंधी आवश्यकताओं के सम्बर्भ में उपयुक्त समझा जाता है। बेहतर पोषण तथा संतुलित आहार व साथ ही नियमित शारीरिक क्रियाकलाप बच्चे के स्वास्थ्य में विकास के प्रति योगदान करते हैं। बच्चों की पोषण-संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैलोरी आवश्यक है। प्रोटीन भोजन में विधमान शरीर-निर्माण तत्व के अवयव हैं जो विभिन्न आहारों में पाए जाते हैं, जैसे दालें, दूध, अंडा, मछली एवं मांस। कैलोरी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है तथा यह अनाज, चीनी, वसा और तैलीय आहारों में उपलब्ध होती है। एक 18 किलोग्राम भर वाले 4 से 6 वर्ष के बच्चे को प्रतिदिन अपने भोजन में 1350 ग्राम कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन और 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। बढ़ती उम्र के साथ बच्चों के पोषण की आवश्यकताये भी बढ़ती है।

बाल्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में अल्प-पोषण के फलस्वरूप बच्चों के विकास में गंभीर बाधाये आती है तथा यह प्रक्रिया जीवन की आगामी अवस्था में भी जारी रहती है। उदाहरण के लिए समय से पूर्व जन्मे और जन्म के समय कम वजन का बालक का विकास निरंतर धीमी गति से होता है तथा वह एक कुपोषित बालक बन जाता है। कुपोषण के कुछ अन्य कारण भी हैं जैसे निर्धनता, निर्मन आय, बाढ़, अकाल तथा नवजात शिशुओं व छोटे बच्चों को माता द्वारा अपना दूध न पिलाना अथवा कम दूध पिलाना इत्यादि।





कुपोषण के निवारण के लिए प्रमुख योजनाये

कुपोषण तथा अल्प पोषण के निवारण के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा कई तरह के कार्यक्रम व योजनाये चलायी जा रही हैं। जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित योजनाये हैं :

योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्षित	प्रदान किये जाने वाले लाभ
समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई. सी. डी. एस.)	गर्भवती और दुध पिलाने वाली माताएँ और 6 साल तक की आयु के बच्चे।	<ol style="list-style-type: none"> आयरन व फोलिक एसिड की गोलियाँ घर ले जाने के लिए राशन स्वास्थ्य व पोषण शिक्षा
इंदिरा गाँधी मातृत्व सहायोग योजना (आईजीएमएसवाय)	भुगतान सहित मातृत्व अवकाश प्राप्त करने वाली महिलाओं को छोड़कर 19 साल या उससे अधिक उम्र की गर्भवती महिलायें।	बच्चे के प्रसव के दौरान वेतन-नुकसान के लिए आंशिक मुआवजे के तौर पर पहले दो जीवित जन्मों बच्चे की देखभाल और सुरक्षित प्रसव व अच्छा पोषण और आहार प्रथाओं के लिए उचित स्थितियां प्रदान करने के लिए 3000 रुपये की नगद सहायता।
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसउसके)	अस्पताल में प्रसव करवाने वाली महिलाएँ और एक वर्ष तक की आयु के बीमार शिशु	<ol style="list-style-type: none"> निःशुल्क व मुफ्त उपचार निःशुल्क दवाएं, निदान व आहार रक्त का निःशुल्क प्रावधान स्वास्थ्य संसाधनों के लिए घर से निःशुल्क परिवहन और उपयोगकर्ता को सभी प्रकार के शुल्कों से छूट
विद्यालयों में निःशुल्क भोजन	स्कूल जाने वाले बच्चे (6 से 14 वर्ष)	<ol style="list-style-type: none"> निधारित मानदंडों के अनुसार मध्यान भोजन। स्कूलों में आयरन और फोलिक एसिड तथा कृमि नाशक गोलियाँ।
किशोरी शक्ति योजना	किशोरियां	स्कूलों में आयरन और फोलिक एसिड तथा कृमि नाशक गोलियाँ।
पोषाहार पुनर्वास केन्द्र (एनआरसी) और कुपोषण उपचार केन्द्र (एमटीसी)	गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे	<ol style="list-style-type: none"> 14 दिन के लिए आहार चिकित्सा के साथ रोगी का इलाज। भोजन और देखभाल प्रथाओं पर माताओं को परामर्श।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली	अन्मयोदय व प्राथमिक वाले परिवार	कम रियायती दरों पर राशन जैसे चीनी, चावल व अनाज।

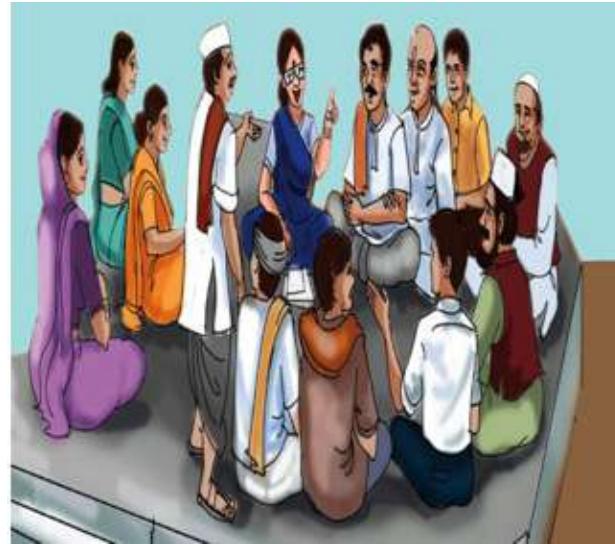


ग्राम पंचायत क्षेत्र में बच्चों का विकास सुनिश्चित करने में पी.अल.सी.पी.सी. की भूमिका :



ग्राम पंचायत के क्षेत्र में बच्चों को उनके विकास के लिए समर्थ अवसर प्राप्त हो इसके लिए पी.अल.सी.पी.सी. को एक निर्णायक भूमिका निभानी होगी। इसके लिए समुदाय में जागरूकता लाना पहला कदम होगा। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समिति, एनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा आदि को शामिल करते हुए ग्राम पंचायत क्षेत्र में अल्प-पोषित बच्चों का पता लगाने के लिए गाँवों का सर्वेक्षण करवा सकती है तथा उसके अनुसार ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार कर सकती है।

- पी.अल.सी.पी.सी.के सदस्य वीएचएसएनसी तथा आंगनबाड़ी स्तरीय अनुबीक्षण और सहायता समिति के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं तथा बच्चों को आंगनबाड़ी में पर्याप्त पोषण प्राप्त हो आंगनबाड़ी में साप्ताहिक आयरन एंड फोलिक सप्लीमेंटेशन के वितरण को आशा / आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सहायता से सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- पी.अल.सी.पी.सी. विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावक शिक्षक संघ की सहायता भी प्राप्त कर सकती है।
- पी.अल.सी.पी.सी. के सदस्य जिनमे से एक सदस्य विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष है अतः वे यह सुनिश्चित करे कि विद्यालयों में मध्याहन भोजन के माप व उसकी गुणवत्ता की जाँच करनी चाहिए और अ ।। व ।। य क मुद्दों को विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की बैठकों में भी उठाना चाहिए।
- समिति समर्थ निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा आंगनबाड़ी विद्यालय के कर्मचारियों, ग्राम स्वास्थ्य व पोषण समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, स्वयं सहायता समूह आदि के प्रशिक्षण सम्बंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में बच्चों / किशोरों के साथ कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।



गतिविधि 2 :-जब करेंगे तब होगा।

संदर्भ व्यक्ति सभी सदस्यों के साथ इस गतिविधि को आयोजित करेंगे। एक पैन को सीधा खड़ा किया जाएगा। इसके सहारे हेतु पुस्तकों या अन्य सामग्री की भी मदद ली जा सकती है। अब सभी को सहभागियों से कहेंगे कि पैन को फूँक मारकर गिराइये। सभी संभागी एक साथ फूँक मारेंगे। लेकिन पैन नहीं गिरेगा। अब सहभागियों से कहेंगे कि सभी ताली बजाकर गिराइये। सभी ताली बजाकर पैन गिराने का प्रयास करेंगे। फिर भी पैन नहीं गिरेगा। फिर सभी को बोलेंगे कि आखें बन्द करके पूरी इच्छा से यह कामना करे कि पैन गिर जाए। सभी आखें बन्द करके पूरी इच्छा से यह कामना करते हैं कि पैन गिर जाए। फिर भी पैन नहीं गिरेगा। अब किसी एक सहभागी से कहेंगे कि वह उठकर जाए और पैन गिरायें। एक सहभागी उठकर जाएगा। और पैन गिरा देगा। गतिविधि के पूरा होने के पश्चात संदर्भ व्यक्ति निम्न बिन्दुओं के आधार पर समूह के साथ चर्चा करेंगे-

- . इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ ?
- . पैन कैसे गिरा ?
- . इस गतिविधि से हमें क्या समझ आया ?

सर्वेक्षण :-

- . संदर्भ व्यक्ति इस प्रकार से सम्बोधित करें कि जो भी कार्य होता है वह कुछ करने से ही होता है, सिर्फ उनके बारे में बातें करने या सोचने से नहीं।
- . ग्राम स्तर पर सभी बच्चों की सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो पायेगी जब बाल संरक्षण समिति के सदस्य अपने अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी रखते हुए उनका पालन करेंगे।

कोई भी ऐसी गतिविधि जो, समुदाय स्वयं या अपनी किसी संस्था के माध्यम से करता है, लेकिन उसके नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन का कार्य समुदाय द्वारा स्वयं सक्रियता के साथ किया जाता है उसे सामुदायिक गतिशीलता कहते हैं। सामुदायिक गतिशीलता किसी भी क्षेत्र में हो सकती है जैसे :- स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा। सामुदायिक गतिशीलता का उद्देश्य जन सामाज्य के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है।





संरक्षण का अधिकार

घर, विद्यालय अथवा अन्यत्र कही भी बच्चों के साथ होने वाली क्रूरता, उपेक्षा, शोषण, दुराचार, परित्याग, आभाव एवं दुर्व्यवहार से बच्चों की रक्षा करना एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना ही बाल संरक्षण कहलाता है। बाल संरक्षण में बच्चों को ऐसी स्थिति से सहायता व् पुनर्वास करना भी शामिल है जब वह किसी असुरक्षित स्थिति का शिकार बन गये हो।

बाल संरक्षण के तीन मुख्य पहलु हैं: पहला ऐसा वातावरण निर्माण करना जिसमें कोई भी बच्चा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या अन्य किसी तरीके से शोषण के साथ दुर्व्यवहार तथा उपेक्षा का शिकार ना हो। दूसरा बच्चों के लिए बाल मैत्री, सकारात्मक एवं सङ्क्रीय ढंगों और प्रक्रियाओं सहित एक सुरक्षात्मक एवं अनुकूल माहौल बनें। तीसरा यह सुनिश्चित करना की एक समुदाय आधारित बाल संरक्षण तंत्र स्थापित करते हुए बच्चों की जलरतों को ध्यान में रखकर उनके अधिकारों का हनन होने पर तुरंत आवश्यक कार्यवाही करें।

इस तरह ये तीनों पहलु साथ में बाल संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के अनुसार बचपन में किसी कथित या वास्तविक खतरे या जोखिम से बच्चों की सुरक्षा करना ही बाल संरक्षण है।

कुछ जोखिमपूर्ण स्थितियां जिनसे बच्चों को बचाने / संरक्षण की जरूरत हैं।

1. बालश्रम :

बालश्रम का अर्थ है पैसा कमाने के उद्देश्य से बच्चे को किसी ऐसे काम में लगाना जो उन्हें उनकी बाल्यावस्था से वंचित करता है, उनको विद्यालय जाने से रोकता तथा बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ उसके विकास के लिए भी खतरनाक हों। बालश्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार किसी भी जोखिमपूर्ण व्यवसाय में 14 वर्ष से कम के बच्चों को रोजगार का प्रतिषेध करता है तथा 14-18 वर्ष तक बच्चों के लिए विभिन्न कार्य-परिस्थितियों को विनियमित करता है।

बालश्रम के कुप्रभाव :

अनेक बच्चे ग्रायः कृषि क्रियाकलापों में, छांबों में और घरेलु नौकरों के रूप में कार्य करते हैं जहां पर वे हिंसा व यौन हिंसा का शिकार बन जाते हैं। उनका विद्यालय जाना छुट जाता है। बाल मजदूरी का एक और बुकसान यह है की जो बाल मजदूरी करवाता है वह बच्चों को कम पैसे देकर काम पर रखता है जिससे जो बड़े काम करने वाले होते हैं उनको रोजगार नहीं मिल पता है अतः इस से बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है।

2. बाल विवाह

बाल विवाह का अर्थ है ऐसा विवाह जो किसी व्यक्ति के व्यस्क होने से पूर्व किया जाता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार बालिकाओं का 18 वर्ष तथा बालकों का 21 वर्ष से पूर्व विवाह गैर-कानूनी माना जाता है हमारे देश में बालिका वधुओं की संख्या सबसे अधिक है लड़कियों को पराया धन माना जाता है उनसे जिन मुख्य भूमिकाओं को निभाने की अपेक्षा की जाती है वे हैं - बच्चों को जन्म देना, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना तथा घर के सभी कार्य करना मगर ऐसा नहीं है अगर बालिकाओं को पूरा अवसर दिया जाये तो वे बहुत आगे निकल सकती हैं उदाहरण के लिये कल्पना चावला, किरण बेदी, इन्दिरा गाँधी आदि कई ऐसी महिलायें हैं जिन्होंने खुद को साबित कर दिखाया है।



बाल विवाह के कुप्रभाव :

बाल विवाह छोटी बालिकाओं को ऐसी आयु में उनके माता-पिता और परिवार से अलग कर देता है जब उन्हें अपने बेहतर विकास के लिए उनकी ज्यादा जरूरत होती है। बाल विवाह के कारण यौन संबंध भी छोटी आयु में ही स्थापित हो जाते हैं जिसकी वजह से कम आयु में माँ बन जाती है उस वजह से होने वाला बच्चा कुपेशित होने का खतरा रहता है।



3. बाल यौन उत्पीड़न :

किसी व्यक्ति अथवा शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने के लिए किसी बच्चे का उत्पीड़न करना। इसकी रोकथाम के लिए लैंगिक अपराधों से बच्चों का सरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार किसी बच्चे के विरुद्ध हुए यौन-उत्पीड़न के मामलों की पुलिस को सुचना दिया जाना अनिवार्य है। सरपंच व ग्राम पंचायत सदस्यों को भी इस तरह की सुचना देना अनिवार्य है।



4. शारीरिक दण्ड :

किसी भी रूप में शारीरिक दण्ड, जिसमें माता-पिता, अभिभावक, शिक्षक आदि द्वारा मारपीट शामिल है। भारत में कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तथा ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है शिक्षकों को कारावास तथा जुर्माना हो सकता है तथा उनकी पदोन्नति व वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है।

5. अवैध व्यापार के शिकार तथा गुमरादा बच्चे :

अवैध व्यापार का शिकार वह बच्चा है जो 18 वर्ष से कम आयु का है, जिसे देश के भीतर अथवा बाहर शोषण के प्रयोजन के लिए रोजगार पर नियुक्त किया जाता है। भारत में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 में पारित किया गया जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करना है।

कुछ बच्चे उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं भोगोलिक स्थिति के कारण दुसरे बच्चों की तुलना में ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है तथा उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ये बच्चे इस प्रकार हैं :

- बेघर बच्चे (फूटपाथ पे रहने वाले, विस्थापित / बेदखल, शरणार्थी आदि)
- प्रवासी बच्चे
- गली में रहने वाले बच्चे
- अनाय / छाड़े जा चुके बच्चे
- काम करने वाले बच्चे
- वैश्याओं के बच्चे
- बाल वैश्याये
- बच्चों का अवैध व्यापार
- संघर्ष से प्रभावित बच्चे
- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बच्चे
- एचआईवीधृडस से प्रभावित बच्चे
- टर्मिनल बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं है
- विकलांग बच्चे
- अनुसूचित जातियों व् जनजातियों के बच्चे



बच्चों की उपेक्षा एवं शोषण से जुड़े कुछ भ्रम :

1. बच्चों का शोषण कभी नहीं किया जाता। समाज बच्चों से बहुत प्यार करता है।

हाँ यह सत्य है की हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं लेकिन अभी भी कुछ कमी है भारत में विश्व के सबसे ज्यादा बाल श्रमिक है, सबसे ज्यादा बच्चों के साथ शोषण होता है तथा 0-6 आयु वर्ग में महिलाओं का अनुपात पुरुषों की तुलना में बहुत कम है इससे पता चलता है की भारत में बालिकाओं का अस्तित्व खतरे में है कभी-कभी बच्चों को बेच दिया जाता है या मार दिया जाता है क्योंकी वो लड़की है।

बच्चों से खिलाफ दर्ज हुए प्रकरण भी एक धिनोनी कहानी पेश करता है यहाँ तक की सरकारी आकड़ों के हिसाब से 2002 से 2003 के बीच बच्चों के खिलाफ दर्ज होने वाले केसों में 11.1% की वृद्धि हुई है।





2. घर बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है :

माता-पिता बच्चों को अपनी जागिर समझते हैं हर दुसरे दिन हम देखते हैं की कोई पिता अपनी ही बेटी को सिर्फ पैसों के लिए बेच देता है ऐसे भी कई मामले सामने आये हैं जो की व्यूज एवं अदालत में भी साबित हुए हैं की कोई पिता खुद अपनी बेटी का बलात्कार करते हैं। कन्या भूर्ण हत्या, देवी-देवताओं के लिए बच्चों की बलि, बच्चों पर हिंसा आदि मामलों से पता चलता है की बेटिया अपने ही घर में कितनी असुरक्षित है।

3. लड़कों की चिंता करने की जरूरत नहीं है ये तो वेसे भी सुरक्षित है

लड़के भी उतने ही असुरक्षित हैं जिनके लड़कियां। लड़कों को घर पर तथा विधालय में शारीरिक एवं मानसिक दंड के शिकार होते हैं उनको कई बार मजदूरी करने के लिए बाहर भेज दिया जाता है या बेच दिया जाता है जहां उनके साथ यौन शोषण होने का खतरा रहता है।

4. ऐसा हमारे गाँव में तो नहीं होता :

हम में से सभी यह सोचते हैं की बच्चों का शोषण, हिंसा, अत्याचार, उपेक्षा आदि कहीं ओर जगह होता होगा हमारे घर या गाँव या समाज में ऐसा नहीं होता। ये सब चीजें दुसरे बच्चों को प्रभावित करती होंगी हमारे बच्चों को नहीं। जबकि वास्तविकता यह है की बच्चों के साथ होने वाले ये सभी दुर्व्यवहार हमारे आस पास भी होते हैं हम बस उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। जरूरत है की हम उसको समझे तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठायें।

ग्राम पंचायत क्षेत्र में बच्चों का सरंक्षण सुनिश्चित करने के लिए पी.एल.सी.पी.सी. की भूमिका:

- बालश्रम निवारण के लिए पी.एल.सी.पी.सी. की भूमिका :
 - बाल मजदूरी करने वाले परिवारों व बाल मजदूरी कर रहे बच्चों की पहचान कर उनको बाल मजदूरी से हटाना तथा ऐसे परिवारों को मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का कार्य अवश्य प्रदान करवाना तथा पात्र लाभार्थियों को सम्बंधित सरकारी योजना से जोड़ना।
 - जोखिमपूर्ण कार्य परिस्थितियों से बच्चों को सुरक्षित करना।
 - समिति की उन परिवारों पर भी ध्यान देना चाहिए जो वर्ष के कुछ महीने मजदूरी के लिए गाँव से बाहर जाते हैं।
 - विद्यालय ना जाने वाले बच्चों को प्रधानाध्यापक के साथ समन्वय स्थापित कर पुनः विद्यालय में दाखिला दिलाना।

 - बाल विवाह से बच्चों का सरंक्षण :
 - ग्राम पंचायत क्षेत्र में हुए समस्त जन्मों का पंजीकरण, जो बाल विवाह के मामले में विवाह की आयु का निर्धारण करने में सहायता प्रदान करता है।
 - समिति को वर्ष की विशिष्ट अवधियों के दौरान बाल विवाह के आयोजनों के बारे में सतर्क रहना चाहिए जैसे राजस्थान में अक्षय तृतीया के दौरान बड़े पैमाने पर बाल विवाह आयोजित किये जाते हैं। समिति विवाह योग्य बच्चों पर निगरानी रख सकती है तथा ऐसा होने पर प्रशासन के साथ मिलकर माता-पिता को पाबंध कर सकती है।
 - विद्यालय के शिक्षकों को इस बात पर नजर रखने के लिए संवेदनशील बनाये की जैसे ही कोई बच्चा स्कूल से नियमित अनुपस्थित रहे तो तुरंत समिति के साथ मिलकर उसकी जाँच करें।
- इसी तरह से बच्चों को अन्य खतरों, यौन उत्पीड़न, शारीरिक दण्ड, अवैध व्यापर आदि से भी बचाया जा सकता है।

आवश्यकता एवं जरूरतमंद बच्चों के लिए भारत सरकार की 24 घंटे की निशुल्क आपातकालीन फोन सेवा है। कोई भी व्यस्क या बच्चा मुसिबत में फंसे बच्चे को बचाने के लिए शुल्क रहित नंबर 1098 डायल कर सकता है। चाइल्ड लाईन न केवल बच्चों की आपातकालिन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। बल्कि उनकी दीर्घकालिक देखरेख और पुनर्वास के लिए उन्हे उपयुक्त सेवाओं से भी जोड़ती है।





सहभागिता का अधिकार

बच्चों को समान व स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, किसी भी तरह की कावूनी जानकारी जानने, बच्चों के विचारों तथा विवेक के प्रति आदर, किसी भी धर्म की मान्यता, संगठन व शांतिपूर्ण सभाएं, सांस्कृतिक गतिविधियों व कलाओं में समान रूप से सहभागिता अधिकार तथा सुचना का अधिकार प्राप्त है। बाल सहभागिता का अधिकार का मतलब है कि बच्चे तथा किशोर उनसे सम्बंधित क्रियाकलापों, प्रतिक्रियाओं और निर्णयों में भाग ले तथा तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप इन्हें संचालित किया जाये बच्चों के पास अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार और क्षमता है व्यस्कों का यह कर्तव्य है की वे उनके विचारों को सुनें तथा परिवार, विधालय और समुदाय में उन्हें प्रभावित करने वाले सभी मामलों में उनकी प्रतिभागिता को मजबूत बनाए।



भागीदारी के मुद्दे :

प्रायः वयस्क लोग यह सोचते हैं कि बच्चे सहभागिता नहीं कर सकते हैं वे सोचते हैं कि :-

- बच्चे अपरिपक्व हैं
- बच्चों को यह नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए
- बच्चों का दुष्टिकोण व्यावहारिक नहीं होता
- बच्चे कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते
- बच्चे किसी कार्य को नहीं कर पायेंगे या ये काम उनसे नहीं होगा या ये काम तो हम बड़ों का है इसमें बच्चों का क्या काम है।

प्रमुख कारण जो बच्चों की भागीदारी और उनकी पसंद को प्रभावित करते हैं :-

- गरीबी
- जाति और धर्म
- लिंग
- शारिरिक व मानसिक विकलांगता
- बच्चे की संवेदनात्मक स्थिति
- अन्य कारण

क्या आपने नहीं देखा है :

- छोटे बच्चे विधालय के वार्षिक दिवस समारोह का आयोजन कर रहे हैं ?
- बच्चे सामाजिक मुद्दों के बारे में स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं ?

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के एक जागरूक सदस्य होने के साथ आप जो भी कार्य करते हैं तब कभी आपको यह महसूस हुआ होगा की यदि आपको आपकी बाल अवस्था में अधिक प्रतिभागिता का अवसर मिला होता तो आप आज की तुलना में एक बेहतर नेता, एक बेहतर आयोजक या कुछ और अच्छा बन पाते।

बच्चों की क्षमताओं का उपयोग तभी किया जा सकता है जब उन्हें भागीदारी करने का अवसर प्राप्त हो।





बच्चों की सहभागिता निर्माणित प्रकार से सहायता करती है :

- विद्यालयों, आंगनवाड़ीयों और पंचायतों से मिलने वाली सेवाओं में सुधार लेने के लिए।
- बच्चों के ज्ञान, व्यक्तित्व और सामाजिक कौशलों का निर्माण करती है तथा नागरिकता और निर्णय लेने के प्रति सकारात्मक अभिवृति तैयार करती है।
- उनके आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि करती है।
- बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान का निर्माण करती है तथा संकटों के संभावित शिकार बच्चों के विरुद्ध भेदभाव को कम करती है।
- अपने सहयोगियों के निर्णयों के प्रति अधिक सम्मान की भावना का निर्माण करती है ! बच्चे यह समझने लगते हैं कि उनसे बड़े लोगों ने कोई निर्णय क्यों किया ।

बच्चों की सहभागिता के विभिन्न मंच

विद्यालय ऐसी संस्था है जो मुख्य रूप से बच्चों के विकास संबंधी आवश्कताओं की पूर्ति करती है तथा उनके व्यक्तित्व का निर्माण करती है

विद्यालय क्लब:

विद्यालय क्लबों में छात्र शामिल होते हैं तथा शिक्षक उनके परामर्श सदस्य अथवा सरंक्षक होते हैं ये क्लब कला, विज्ञान, साहित्यिक, व्यावसायिक और सामाजिक क्षेत्रों से सम्बन्धित होते हैं बच्चे अपने मन पसंद क्रियाकलापों को करने के लिए इसमें शामिल होते हैं इसके फलस्वरूप विद्यालय में बच्चों की विभिन्न क्रियाकलापों में संवर्धित प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हैं



विद्यालय संसद/बाल समूह

अनेक विद्यालयों में विद्यालय संसद अथवा छात्र समूह होती है जो विद्यालय के छात्रों का निर्वाचित निकाय है विद्यालय सांसदों के माध्यम से बच्चों में नेतृत्व, प्रतिभागिता, निर्णय लेना और कौशलों को सीखते हैं यह बच्चों को लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा प्रक्रिया को समझने में मदद करती है।

बाल ग्राम सभा

बाल ग्राम सभा का उद्देश्य ग्राम पंचायत की स्थानीय आयोजना प्रक्रिया में बच्चों की लोकतान्त्रिक भागीदारी को सुदृढ़ बनाना है बाल ग्राम सभा 10 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का वार्ड स्तरीय समूह होता है जिसका मुख्य उद्देश्य बाल विकास होता है ऐसे मंच सभी जाति व धर्मों के बच्चों के लिए समान रूप से खुले होते हैं।

पी.अल.सी.पी.सी. में सहभागिता

पी.अल.सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार समिति में दो बाल प्रतिनिधि होते हैं जिनमें 14 वर्ष से ऊपर का एक बाल व एक बालिका शामिल हते हैं





बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समिति की भूमिका

ग्राम पंचायत क्षेत्र में बच्चों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए समिति निम्नलिखित कदम उठा सकती है

- पंचायत क्षेत्र में आने वाले सभी गाँवों में नियमित बाल ग्राम सभा का आयोजन सुनिश्चित करना तथा उनमें आये मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना
- समिति के सदस्य मिलकर यह सुनिश्चित करे की गाँव में बच्चों के खेलने के लिये उधान, मैदान आदि की समुचित व्यवस्था हो !
- पंचायत स्तर पर बच्चों के अनेक विशेष दिवसों जैसे बाल दिवस, बालश्रम निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आदि को मनाया जाये।

इनके अलावा भारत का नागरिक होने के नाते उनको दुसरे नागरिकों की भाँती कुछ और अधिकार भी प्राप्त हैं जो इस प्रकार है :

- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14)
- भेदभाव के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15)
- व्यतिगत स्वतंत्रता एवं कानून की प्रक्रिया का अधिकार (अनुच्छेद 21).
- तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर करने से सुरक्षा का अधिकार. (अनुच्छेद 23)
- समज के कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 46).

भारत के सविंधान द्वारा सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि वे आवश्यक रूप से

- महिलाओं एवं बच्चों के विशेष प्रावधान करें (अनुच्छेद 15 (3)).
- अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा (अनुच्छेद 29).
- समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 46)
- लोगों के पोषण, स्वास्थ्य स्तर एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयास करना (अनुच्छेद 47).

भारत के सविंधान के अलावा भी कई ऐसे कानून हैं जो मुख्य रूप से बच्चों के लिए हैं। अतः समिति के एक जागरूक सदस्य होने के नाते आपको उनके महत्व के बारे में पता होना चाहिए। इस मार्गदर्शिका के साथ में विभिन्न वर्गों में उनका उल्लेख किया गया है।

गतिविधि 3 :

संदर्भ व्यक्ति सभी सदस्यों से मकान बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा करें जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों की सहायता ली जाती हैं।

- . यदि हमें मकान बनवाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे
- संभावित उत्तर :- मकान का नक्शा बनाना, बजट बनाना, बनाने वाले व्यक्ति का चयन करना और सामग्री की व्यवस्था करना इत्यादि।
- . मकान बनाने समय आप क्या करेंगे ?
- संभावित उत्तर :- काम समय पर व सही प्रकार से हो रहा है नहीं इस बात की देखें-ऐसे करेंगे, मजदूरों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर नजर रखेंगे, आवश्यक सामग्री की उपयोगिता व उपलब्धता को देखेंगे।
- . मकान बनाने के पश्चात् आप क्या करेंगे ?
- संभावित उत्तर :- मकान सही प्रकार से बना है या नहीं बना यह सुनिश्चित करेंगे व उसके पश्चात् भुगतान करेंगे।

आप मकान बनाने के कार्य में इतनी लूचि दिखाते हैं क्योंकि इसमें सीधे आपके हित जुड़े हैं। इसी प्रकार यदि गाँव में बच्चों के हितों की रक्षा की जाये तथा बच्चों के अधिकारों का हनन न हो तो इसमें भी गाँव का व समुदाय का सीधा सीधा लाभ है क्योंकि बच्चे जितने सुरक्षित वातावरण में रहेंगे उतने ही अच्छे से शिक्षा ग्रहण करेंगे तथा अच्छे नागरिक बनकर देश व समाज की सेवा करेंगे। यह सत्य है कि चाहे कोई भी योजना कितनी भी अच्छी क्यों न बनायी जाए जब तक उसमें समुदाय की सकारात्मक भागीदारी नहीं होगी, तब तक वह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। इस बात को ध्यान में रखते हुए किशोर व्याय अधिनियम, 2000 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत विभिन्न स्तरों जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है तथा उन्हें उचित शक्तियां दी गई हैं ताकि समितियां अपने गाँव की बेहतरी के लिए स्वयं योजना बना सकें, लागू कर सकें और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें।

निष्कर्ष :- सहभागियों में बच्चों के विकास के लिए सामुदायिक सहभागिता के महत्व पर एक प्रारम्भिक समझ विकसित हो पाएगी तथा वे बाल मैत्री गाँव के विकास एवं बच्चों के संरक्षण में अपने को एक हितभागी के रूप में समझें।



ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति



ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति : एक परिचय

राज्य सरकार द्वारा बच्चों की देखभाल एवं सरंक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं सरंक्षण) अधिनियम, 2000 एवं समेकित बाल सरंक्षण योजना का क्रियावान किया जा रहा है। समेकित बाल सरंक्षण योजना के अंतर्गत देखभाल एवं सरंक्षण की आवश्कता की श्रेणी में आने बच्चों का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करने, बाल अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम एवं उनके स्वस्थ शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए समुदाय एवं ग्राम पंचायत की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विभिन्न कार्यकर्त्ताओं एवं योजनाओं पर सतत निगरानी रखने एवं उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं आवश्यक अनुशंशा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्थर पर ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का नूनी प्रावधान

किशोर न्याय अधिनियम, 2000 एवं समेकित बाल सरंक्षण योजना के तहत विभिन्न स्तरों, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन का प्रावधान है। इसलिए पीएलसीपीसी, आईसीपीएस के तहत राज्य सरकार द्वारा एक पहल माना जाता है।

सरकार द्वारा ऐसी समितियों का गठन अधिसूचना का माध्यम से किया जाता है। यह एक ऐसी समिति है जिसमें समुदाय के लोगों की, सरकारी विभागों का समर्थन, विद्यालयों एवं बालकों की भागीदारी सुनिश्चित करती है जिससे समिति की प्रभावी क्षमता, सामाजिक एवं नैतिक प्रतिबधता का पता चलता है।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के उद्देश्य

पीएलसीपीसी के गठन का मुख्य उद्देश्य गाँव व समुदाय में बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण निर्माण करना है साथ ही समिति अपने क्षेत्र में बाल सरंक्षण कार्यकर्त्ताओं के प्रभावी क्रियावन सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार उत्तरदायी एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगी :-

- अ. समिति ग्राम पंचायत क्षेत्र में बाल सरंक्षण से जुड़े कार्यकर्त्ताओं के प्रभावी क्रियावन, समन्वय, निगरानी, नियंत्रण एवं सुधार के लिए कार्य करेगी।
- ब. समिति द्वारा देखभाल एवं सरंक्षण की आवश्कता वाले बच्चों के चिन्हीकरण, बच्चों हेतु मोजूद संस्थाओं/ गृहों/ विद्यालयों / आंगनवाड़ी केन्द्रों का सतत निरिक्षण कर आवश्यक सुधार हेतु कार्य करेगी।
- स. बच्चों के सरंक्षण एवं विकास के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ बच्चों को दिलवाने के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक प्रयास करेगी।
- दृ स्थानीय स्तर पर बच्चों के साथ होने वाले दुर्बलवाहार, शोषण, हिंसा एवं उपेक्षा से सम्बंधित मुद्दों पर उनके सुरक्षा एवं अधिकारों के सरंक्षण हेतु निर्णय लेते हुए सम्बंधित संस्थाओं (बाल संरक्षण समिति विशेष किशोर पुलिस ईकाई) तक मामलों को पहुंचायेगी एवं उनका फॉलोअप करेगी।
- य. समिति बाल अधिकारों के बारे में प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करते हुए बाल मैत्री ग्राम का निर्माण करेगी।





ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन एवं मजबूतीकरण

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का कार्यक्रम

एक पीएलसीपीसी आदर्श रूप से हर ग्राम पंचायत पे बनती है तथा उस पंचायत क्षेत्र में आने वाले सभी राजस्व गाँव पीएलसीपीसी का कार्यक्षेत्र होता है। अतः यह कह सकते हैं की सम्बन्धित पंचायत में 18 वर्ष तक की आयु के सभी बालक एवं बालिकाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी पीएलसीपीसी का कार्यक्षेत्र है।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन

समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्कता की श्रेणी में आने बच्चों का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करने, बाल अधिकारों के उल्लंगन की रोकथाम एवं उनके स्वस्थ शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए समुदाय एवं ग्राम पंचायत की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विभिन्न कार्यकर्ता एवं योजनाओं पर सतत निगरानी रखने एवं उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं आवश्यक अनुशंसा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्थर पर ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है। अतः यह एक समुदाय आधारित सरकारी तंत्र है जिसका गठन गाँव स्तर पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी

क्र.स.	सदस्य का नाम	समिति में पद
1	संरपंच, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2	ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत	सचिव
3	वार्ड पंच (समस्त)	सदस्य
4	प्रधानाध्यापक, स्थानीय राजकीय विद्यालय (प्रारंभिक शिक्षा)	सदस्य
5	बाल कल्याण अधिकारी, संबन्धित पुलिस थाना	सदस्य
6	जिला बाल संरक्षण ईकाई का सदस्य (सहा. निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाई द्वारा नोमित)	सदस्य
7	ए. एन. एम. ग्राम पंचायत	सदस्य
8	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत	सदस्य
9	अध्यक्ष संबन्धित शाला प्रबंधन समिति, स्थानीय राजकीय विद्यालय (प्रारंभिक शिक्षा)	सदस्य
10	दो बाल प्रतिनिधि (कम से कम एक बालिका) प्रधानाध्यापक द्वारा नोमित	सदस्य
11	समुदाय के दो सम्मानित सदस्य/नागरिक (कम से कम एक महिला)	सदस्य

नोट :

- समिति में समुदाय के दो सम्मानित सदस्य नागरिकों का चयन सम्बन्धित प्रधान, पंचायत समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होगा।
- ग्राम पंचायत स्तरीय बाल सुरक्षा समिति की रूपरेखा में बिंदु संख्या 10 में प्रधानाध्यापक द्वारा नामित दो बाल प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में विद्यालय की उच्च कक्षा में अध्यनरत दो विधार्थियों का चयन किया जायेगा।





समिति में पदाधिकारी एवं उनकी जिम्मेदारियाँ अध्यक्ष की जिम्मेदारिया

- I. समिति को नेतृत्व प्रदान करना।
- II. समिति के लिए प्रवक्ता के रूप में कार्य करना।
- III. यह सुनिश्चित करना की समिति की बैठके हर महीने निरंतर होती रहे।
- IV. बाल संरक्षण के अन्य तंत्र जैसे पीआरआई, सीपीसी, सरकारी अधिकारी आदि से संपर्क बनाये रखना।
- V. पंचायत के लिए बाल संरक्षण वार्षिक योजना तैयार करना।
- VI. समिति द्वारा अनुमोदित बाल संरक्षण गतिविधियों एवं कार्यकर्मों के संचालन के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना एवं समय पर उन संसाधनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- VII. आवश्यकता अनुसार सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के साथ सामंजस्य स्थापित करना।

सचिव की जिम्मेदारी

- I. अध्यक्ष को सभी कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
- II. सभी सदस्यों को प्रस्तावित एजेंडे की एक प्रति के साथ-साथ प्रत्येक बैठक का नोटिस जारी करना।
- III. प्रत्येक बैठक का उपस्थिति का दस्तावेज एवं ब्यौरा बनाना।
- IV. समिति की तरफ से सभी सम्बंधित विभाग एवं अधिकारियों को आवश्यक पत्र एवं प्रतिवेदन भेजना।
- V. समिति द्वारा किये गए किसी भी प्रकार के खर्चों के बिलों को स्वीकृत करना।
- VI. समिति की हर प्रकार की रिपोर्टिंग एवं प्रेलेखन करना।

सदस्यों की जिम्मेदारियाँ

पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समुदाय में बच्चों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण बनाने में समिति के सदस्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है

- I. सभी सदस्यों की यह जिम्मेदारी रहेगी की वे सभी बैठकों में नियमित रूप से हिस्सा ले तथा बैठक में होने वाली चर्चा एवं विचार विमर्श में सक्रीय रूप से हिस्सा ले।
- II. वह समिति के नियमों का पालन करें।
- III. वह निश्चित तौर से बाल संरक्षण आचार संहिता का पालन करें तथा इसका उल्लंघन होने पर रिपोर्ट करें।
- IV. वह सक्रीय रूप से समिति की जागरूकता बढ़ाने तथा अन्य गतिविधियों में भाग ले।
- V. वह समिति द्वारा दी सौपी गयी जिम्मेदारियों का पूर्ण झूमानदारी से निर्वहन करें।
- VI. सदस्य स्वयं अपने घर तथा समुदाय में ऐसे उदाहरणपेश करे जिनमें बच्चे पूर्ण रूप से सुरक्षित हो।
- VII. वह बाल-विवाह, कन्या भूषण हत्या, बाल श्रम, बच्चों के साथ अभद्रता, बाल उत्पीड़न शारीरिक दंड, जाति व धर्म के आधार पर भेदभाव आदि घटनाओं में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं हो अपितु इनको रोकने के लिए प्रयास करें।
- VIII. वह समुदाय में बच्चों पर सीधे तौर से निगरानी रखता है तथा स्वयं अथवा समिति के माध्यम से उपर्युक्त अधिकारी एवं विभाग को रिपोर्ट करें। हालांकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समिति के हर सहभागी की ऊपर लिखी गयी सभी जिम्मेदारियाँ हैं।





मीटिंग एवं कोर्स

समिति प्रत्येक माह में अपनी बैठक आयोजित कर कार्यवाही विवरण रजिस्टर में दर्ज कर कार्यवाही विवरण की प्रति अनिवार्यता से जिला बाल संरक्षण इकाई / पंचायत समिति स्तरीय बाल संरक्षण समिति को प्रेषित करेगी।

प्रत्येक बैठक में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति में किये गए निर्णय ही वैध व मान्य होंगे। समिति के सदस्यों द्वारा किये गए कार्यों का अनुमोदन (पूर्व/पश्चात) किया जाना आवश्यक है।

दस्तावेजीकरण एवं रिपोर्ट लेखन

किसी भी प्रशिक्षण या बैठक में दस्तावेजीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अगर दस्तावेजीकरण सही तरीके से तथा जिम्मेदारी से नहीं किया जायेगा तो वह बैठक या प्रशिक्षण लम्बे समय तक लाभदायक नहीं रहती। अतः समिति अध्यक्ष सूत्रधार तथा अन्य सदस्यों की मदद से दस्तावेजीकरण एवं प्रतिवेदन की जिम्मेदारी किसी सक्षम सदस्य दे दस्तावेजीकरण के लिए निम्नलिखित मुख्य दस्तावेज एवं प्रतिवेदन तैयार किये जा सकते हैं :

- बैठक ब्यौरा : हर एक बैठक के मुख्य बिन्दुओं को लिखते जाये
- पंचायत / ग्राम बाल संरक्षण योजना
- पंचायत के सभी गाँवों की रूप-रेखा (गाँव डायरी की मदद ली जा सकती है)
- प्रकरण प्रबंधन रजिस्टर (बच्चों से जुड़ा कोई भी प्रकरण)
- अन्य दस्तावेज तथा आवश्यकता के अनुसार प्रतिवेदन (सफलता की कहानीया)

सन्दर्भ व्यक्ति यह ध्यान रखे की किसी जिम्मेदार साथी को यह महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी सौंपें।

पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के महत्वपूर्ण दायित्व :

समिति अपनी पंचायत एवं सदस्यों के साथ मिलकर मुख्य रूप से दो श्रेणियों के तहत गाँव/समुदाय के बच्चों की स्थिति पर एक आधारभूत आंकलन करे तथा रिपोर्ट तैयार करे अर्थात् “विधि से संघर्षरत बच्चे तथा देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे” इनकी समेकित जानकारी अपने पास रखे तथा जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाये जैसे :

कमजोर बच्चे (बच्चे का नाम लिंग, उम्र, माता-पिता का नाम, गाँव का नाम, नामांकन की स्थिती, व्यक्तिगत जरूरत तथा किसी योजना के लिए लिए उसकी पात्रता)।

आंगनवाड़ी सहित गाँव में शिक्षा के बुनियादी ढंगे और सुविधाये तथा उनकी स्थिति।

गाँव में बाल श्रमिकों की संख्या (व्यवसाय, लिंग व् उम्र के अनुसार)।

पंचायत में कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी जिसको किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो उसकी सम्पूर्ण जानकारी पुलिस से लेना।

ऐसे लोगों की जानकारी इक्कठा करना जिन्होंने बच्चों के खिलाफ कोई अपराध किया हो अथवा उस पर कोई ऐसा कोई केस चल रहा हो।

पंचायत में लिंगानुपात की स्थिति।

गाँव में बच्चों के लिए खेलने, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं मनोरंजन की सुविधाओं से सम्बंधित।

क्षेत्र में काम कर रही कोई भी समुदाय आधारित संघटन या कोई स्वेच्छिक संस्था तथा योजनाओं की जानकारी रखना।

बच्चों के अधिकारों को मानव अधिकार के रूप में समझे तथा अन्य लोगों में भी जागरूकता फैलाये।

नियमित रूप से बच्चों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को ग्राम सभा में उठाये।





इस आंकलन रिपोर्ट में बच्चों से जुड़ी मौजुदा योजनाओं (सरकारी / गैर सरकारी) की गुणात्मक तथा संख्यात्मक जानकारी होनी चाहिए। समिति यह रिपोर्ट अपने कार्यकाल शुरू होने के छः माह के भीतर बना ले तथा इसे प्रत्येक साल निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा अधिकारियों से संपर्क कर अपडेट कर ले:

- सम्बंधित सरकारी विभाग के सक्षम अधिकारी से
- क्षेत्र में मूलभूत सुविधा प्रदाताओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, एन.जी.ओ. आदि)
- बच्चों का गाँव में गठित बाल समूह
- गाँव में सबसे पुण्यना संचालित स्वयं सहायता समूह.
- पंचायत स्तर पर गठित अन्य समितिया
- सहयोगकर्ता



बाल संरक्षण एवं सम्बंधित सेवाओं में संबंध

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन धरातल स्तर पर बाल संरक्षण तंत्र के रूप में अन्य सम्बंधित अधिकारियों एवं विभागों के साथ मिलकर कार्य करने की परिकल्पना के साथ किया गया है। अतः समिति निम्नलिखित विभागों एवं अधिकारियों के साथ मिलकर धरातल स्तर पर बाल सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है।

विद्यालय परिसर में बच्चों के साथ अभद्रता या शारीरिक दंड की स्तिथि में:

सबसे पहले समिति को विद्यालय प्रबंधन समिति से मिलकर मामले को स्थानिय स्तर पर सुलजाने का प्रयत्न करना चाहिये। पत्र को ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी / जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को भेजे तथा एक प्रति जिला कलेक्टर, शिक्षा निदेशालय या बाल सुरक्षा हेतु राज्य आयोग में तथा किशोर व्याय बोर्ड अधिनियम, 2000 के अंतर्गत जिला स्तर पर नियुक्त जिम्मेदार अधिकारी को भेजे।

स्वास्थ्य:

कोई भी शिकायत / जाँच पत्र / सुझाव, संबंधित स्वास्थ्य केंद्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दे तथा साथ ही एक प्रती मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला कलेक्टर तथा जे.जे. एक्ट के तहत सक्षम अधिकारी को भेजे।





बाल संरक्षण :

ऐसे बच्चों से जुड़े मुद्दे जिनको संरक्षण एवं देखभाल की ज़रूरत हो तो ज़िले की बाल कल्याण समिति / चाइल्डलाइन (1098 टोल फ्री आपातकालीन नंबर) / स्थानीय पुलिस (किशोर / बाल कल्याण अधिकारी) / ज़िला बाल संरक्षण ईकाई / ज़िला बाल संरक्षण समिति/ किशोर व्याय बोर्ड आदि से संपर्क करें।

बाल श्रम :

आस पास में किसी भी बच्चे को बालश्रम करते देखे तो तुरंत श्रम निरीक्षक/ चाइल्डलाइन (1098 टोल फ्री आपातकालीन नंबर) / स्थानीय पुलिस (किशोर / बाल कल्याण अधिकारी) / ज़िला मजिस्ट्रेट / ज़िला बालश्रम टास्क फोर्स से संपर्क करें।

बाल विवाह :

बाल विवाह निषेध अधिकारी (स्थानीय तहसीलदार / मुख्य व्यायिक मजिस्ट्रेट / राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिकारी)।



आवश्यकता एवं ज़रूरतमंद बच्चों के लिए भारत सरकार की 24 घंटे की निशुल्क आपातकालीन फोन सेवा है। कोई भी व्यस्क या बच्चा सेवा का लाभ उठाने के लिए शुल्क रहित नंबर 1098 डायल कर सकता है। चाइल्ड लाइन न केवल बच्चों की आपातकालिन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। बल्कि उनकी दीर्घकालिक देखरेख और पुनर्वास के लिए उन्हें उपयुक्त सेवाओं से भी जोड़ती है।





गतिविधि - 3

आवश्यक सामग्री : मौड़यूल की प्रति, पेन, रजिस्टर

पहले संदर्भ व्यक्ति आस-पास की 20-30 वस्तुएँ इकट्ठा करे और एक चादर से ढक देंगे। फिर संदर्भ व्यक्ति सम्भालियों को चार समूहों में बांट देंगे। संदर्भ व्यक्ति निर्देश दें कि इस चादर के नीचे कुछ वस्तुएँ रखी हैं। पहले समूह एक आयेगा और एक मिनट में वस्तुओं को देखेगा और समूह 2 को जाकर दो मिनट में बताएगा। इसके बाद समूह दो सुनी हुई चीजों के नाम समूह तीन को जाकर बताएगा। अंत में समूह तीन बड़े समूह में चीजों के नाम बतायेगा। गतिविधि प्रारम्भ करने से पूर्व संदर्भ व्यक्ति तीनों समूहों हो निर्देश देंगे कि उन्हें योजना बनाने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाता है। और आप अपने समूह में चर्चा कीजिए या योजना बनाये कि यह कार्य अच्छे से कैसे पूरा किया जा सकता है? 5 मिनट बाद गतिविधि को क्रियान्वित करायें। ध्यान रहे कि चादर के नीचे रखी चीजें सिर्फ समूह एक के सम्भागी ही देखे अन्य समूह नहीं देख पायें।

अन्त में समूह तीन द्वारा बताये गए नामों को श्यामपट्ट पर लिखे और चादर हटाकर वस्तुएँ दिखाएं। इस गतिविधि के संपादन के लिए समूहों द्वारा बनायी गई योजना जानने के लिए निम्न सवाल पूछे और संक्षेप में चर्चा करें।

- 1- आपने चीजों के नाम याद रखने के लिए क्या किया ?
- 2- प्रत्येक समूह ने अन्य समूह को नाम बताने के लिए क्या किया ?
- 3- सभी समूहों के नाम याद रखने के लिए क्या तरीका अपनाया ?
- 4- क्या सभी वस्तुओं के नाम बोर्ड पर आयेगा कितनी वस्तुओं के नाम बचे ?
- 5- सभी वस्तुओं के नाम नहीं आ पाने का क्या कारण रहा ?
- 6- क्या आपकी योजना सही थी ? क्या आप इसके अतिरिक्त और भी कुछ कर सकते थे ?

यहां एक-एक प्रश्न पर एक-दो मिनट लगाकर आगे बढ़ते जाए और अंतिम प्रश्न पर तीन से पांच मिनट की चर्चा करें। संदर्भ व्यक्ति कोशिश करें कि संभागी समझ पाये कि अगर वे बेहतर योजना बनाते तो यह कार्य बेहतर तरीके से हो सकता था।

गतिविधि - 4

संदर्भ व्यक्ति संभागियों से सवाल पूछे कि हम हमारी दैनिक जिन्दगी में कहां-कहां योजना बनाकर काम करते हैं? सम्भागियों के जवाब को प्रोत्साहित करते हुए शादी या खेतीबाड़ी में से एक उदाहरण लेकर योजना बनाकर काम करने पर 10 मिनट चर्चा करें जैसे -:

1. शादी/खेतीबाड़ी करने के लिए क्या-क्या तैयारी करनी होती है?
2. तैयारी में समय का ध्यान कैसे रखते हैं?
3. तथ समय में काम पुरा करने के लिए क्या संसाधनों / व्यवस्थाओं की जरूरत होती है।
4. अगर इतनी तैयारी नहीं करें तो काम अच्छा हो पाएगा।

संदर्भ व्यक्ति यहां जोर देकर योजना बनाने की उपयोगिता बतायें कि सभी महत्वपूर्ण कार्यों को योजना बनाकर करने से कार्य तथ समय पर पूरा हो पाता है। साथ ही नतीजे भी बेहतर निकलते हैं जैसे शादी का उल्लास के साथ समापन या किसान बहुत अच्छी उपज प्राप्त कर पाते हैं।





समयावधि :- 75 मिनट

उद्देश्य :-

- बाल मैत्री गाँव की संकल्पना को समझना।
- बाल मैत्री गाँव को बनाने में सभी सदस्यों की भुमिका व सहभागिता को समझना।

आवश्यक सामग्री - मार्कर, 1 चार्ट, स्कैच पैन, सैलो टेप इत्यादि।

क्रियाविधि :-

इस सत्र में एक गाँव की स्थिति और उसमें बच्चों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हुए बाल संरक्षित गाँव के स्वरूप पर काम करें।

संदर्भ व्यक्ति संचालन की भूमिका बनायें कि हम सभी हमारे गाँव एवं पंचायत को बाल संरक्षित बनाने के लिए एकत्रित हए, है। हम सभी मिलकर यह समझने की कोशिश करें कि हमारे गाँव में बच्चों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में समिति की क्या क्या भूमिका हो सकती हैं।

संदर्भ व्यक्ति नीचे दी गई “xyz गाँव” की काल्पनिक स्थिति सहभागियों को सुनाएं और सुनिश्चित करें कि सभी सहभागी केस स्टडी को समझ पाएं।

xyz गाँव :-

xyz एक गाँव है। गाँव की कूल जनसंख्या 1000 हैं। उसमें से 600 पुरुष व 400 महिलाये हैं। गाँव में बच्चों की कूल जनसंख्या 400 हैं। गाँव के विद्यालय में 150 बच्चों का नामांकन है इसमें से योजना 40-50 बच्चे ही स्कूल आते हैं। बाकी बच्चे गलियों में खेलते रहते हैं, कुछ लड़कियां घर और खेत में काम करने के कारण नहीं आ पाती हैं। विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों की भी कभी-कभी शिकायतें आती हैं कि उन्हें विद्यालय में शिक्षकों द्वारा मार-पीट तथा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। 50 बच्चे गुजरात में कॉटन मील में काम करते हैं, 50 बच्चे पास के शहर में होटल व दुकानों पे कार्य करते हैं तथा 50 बच्चों का विवाह हो चूका है। 100 बच्चे ऐसे हे जो ना तो विद्यालय जाते हैं नाहीं कहीं मजदूरी करते हैं वो बस घर पर ही रहते हैं तथा कुछ खेत पर जाते हैं अपने माता-पिता के साथ व कुछ लड़कियां अपने छोटे भाई-बहिनों को सम्भालती हैं। गाँव में बहुत से परिवार तथा लोग ऐसे हैं जो कई योजनाओं के लिए पात्र हैं पर उन्हें उन योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है।

संदर्भ व्यक्ति केस स्टडी को धीरे-धीरे पढ़े। अगर किसी सदस्य को कुछ समझ नहीं आया हो तो दुबारा पढ़ कर सुनाये तथा यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रतिभागी उसको अपनी नोट बुक में लिखते रहे। केस स्टडी सुनाने के बाद संदर्भ व्यक्ति सभी सदस्यों से निम्नलिखित प्रश्न पुछकर चर्चा करें।

प्रश्न - 1 xyz गाँव में क्या-क्या समस्या नजर आ रही है ?

संदर्भ व्यक्ति इस प्रश्न पर 20 मिनट तक चर्चा करते हुए सभी सहभागियों के जवाबों को निम्नलिखित क्षैत्रों के अनुसार चार्ट पर लिखें। यह क्षैत्र हैं :-

(अ) बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी (ब) बच्चों की अच्छी पढ़ाई -लिखाई से जुड़ी।

(स) गाँव में सुविधाओं से जुड़ी। (द) गाँव में बच्चों के लिए रहने का माहौल।

संदर्भ व्यक्ति यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रतिभागी (महिला-पुरुष) समान रूप से सक्रिय भागीदारी करें इसके लिए कोशिश करें कि सभी सहभागियों से प्रश्न पुछे जों और जवाब देने के लिए आग्रह करें।



अब संदर्भ व्यक्ति दूसरे प्रश्न पर चर्चा करें, प्रश्न निम्नानुसार हैः-

प्रश्न - 1 आप ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्य हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या कोशिश करेंगे ?

संदर्भ व्यक्ति 20 मिनट चार्ट पर लिखी गांव की समस्याओं के समाधान पर चर्चा करें। यहां एक क्षैत्र समस्या के समाधान पर चर्चा करें और प्रयास करें कि छोटे छोटे करीय प्रयासों को रेखांकित किया जा सके। सभी समाधानों को चार्ट-2 पर लिखते जाएं साथ ही साथ अन्य सहभागियों द्वारा इन समाधानों पर सहमति - असहमति की राय लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ायें। यदि सहभागियों द्वारा किसी समस्या का समाधान प्राप्त नहीं होता है तो संदर्भ व्यक्ति निम्नांकित संभावित समाधान करें एवं सभी की सहमति-असहमति प्राप्त नहीं की राय लें।

इस प्रकार सन्दर्भ व्यक्ति अपने विवेक से स्थानीय स्तर पर संभावित समाधान की सुची बना सकते हैं। अब सन्दर्भ व्यक्ति तीसरे प्रश्न पर चर्चा करें-

- 1 बच्चों की सुरक्षा : गाँव के सभी बच्चे सुरक्षित रहे उसके लिए समिति यह ध्यान रखे की किसी भी बच्चे के साथ अन्याय न हो अगर ऐसी स्थिति हो तो तुरंत सम्बंधित अधिकारी या पुलिस विभाग से संपर्क करें।
- 2 बच्चों की अच्छी पढाई-लिखायी - पी.एल.सी.पी.सी. के सदस्य विद्यालय के शिक्षकों तथा विधालय प्रबंधन समिति के साथ मिलकर अभिभावकों से बातचित करके 100% नामांकन एवं ठहराव हेतु प्रयास कर सकते हैं।
- 3 गाँव में भौतिक सुविधाएँ : पी.एल.सी.पी.सी सदस्य स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सुधार ला सकते हैं।
- 4 पी.एल.सी.पी.सी की प्रति माह बैठक हो एवं इसका गठन लोकतान्त्रिक तरीके से किया या हो।

प्रश्न-3 एक

आदर्श बाल मैत्री गाँव कैसा होना चाहिए

यहां संदर्भ व्यक्ति समुह से यह भी कह सकते हैं कि xyz गांव बहुत अच्छा गाँव हो जाये तो वहां क्या क्या अच्छी बातें दिखेंगी इस प्रश्न पर 20 मिनट तक चर्चा करें और चर्चा के बिन्दु चार्ट पर लिखते जाएं। संदर्भ व्यक्ति अपनी चर्चा को इन बिन्दुओं पर केंद्रित करें।

बाल मैत्री / बाल हितैषी ग्राम पंचायत :

अब जब हमने बच्चों से जुड़े विभिन्न मुद्दों तथा समस्याओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए अध्ययन कर लिया है व बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पी.एल.सी.पी.सी. कि भूमिका के बारे में भी जान लिया है, क्या आप जानते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत भी ”बाल-मैत्री“ बन सकती है ?

बाल मैत्री ग्राम पंचायत बहुत है जहाँ :

- सभी जरूरतमंद बच्चों तथा परिवारों को सम्बंधित सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।
- विद्यालय में बच्चों के समूह बने तथा नियमित रूप से कार्य करे साथ ही बाल ग्राम सभा का आयोजन हो।
- गाँव में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, कोई भी बच्चा बालश्रम में ना हो तथा किसी भी बच्चे का बाल विवाह नहीं हो।
- बच्चे सुरक्षित तथा सम्मानित महसूस करे वे शिक्षा, खेल व मनोरंजन का लाभ उठाये और उनको अपनी राय व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो।

संदर्भ व्यक्ति उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार बाल मैत्री से सम्बन्धित छोटे छोटे उदाहरणों और सूचकों पर चर्चा करें।

प्रतिभागियों को यह मदद करें कि यह छोटे छोटे बातें किसी भी गाँव को अच्छा बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं।।





सहयोगकर्ता कि भुमिका

- पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन व मजबूतीकरण में सहयोगकर्ता का बहुत महत्वपूर्ण योग है क्योंकि यह समिति समुदाय आधारित बाल संरक्षण प्रणाली है। सहयोगकर्ता समिति का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, मगर इसका मतलब यह नहीं की अगर सहयोगकर्ता नहीं होगा तो समिति कमज़ोर पड़ जाएगी। समिति अपने आप में एक बहुत मजबूत संगठन है फिर भी समिति का एक अभिन्न अंग होने के नाते सहयोगकर्ता को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।
- गाँव की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति तथा गाव के अन्य वर्गों (जाति, वर्ग, धर्म, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि) एवं ग्राम में विकास के मुद्दों के लिए अपनी संवेदनशीलता को समझें।
- उसका दृष्टिकोण गैर पक्षपातपूर्ण, धर्मनिरपेक्ष और लचीला होना चाहिए।
- अगर फैसीलिटेटर स्थानिय है तो ज्यादा से ज्यादा स्थानिय भाषा का प्रयोग करे तथावहा की संस्कृति का सम्मान करे।
- समिति के सभी सदस्यों में एकता बना कर रखे तथा सभी सदस्यों से निरंतर संपर्क बनाये रखे।
- दैनिक डायरी बनाये तथा उसमें रोजाना की गतिविधिया लिखते रहें।
- समिति को सामान्य, वार्षिक, बैठक प्रतिवेदन तथा अन्य दस्तावेज बनाने में मदद करें।
- सदस्यों के साथ बाल अधिकारों पर निरंतर अपडेट साझा करें।
- पंचायत स्तरीय बाल सुरक्षा समिति तथा बाल संरक्षण से सम्बंधित सरकारी विभागों के बीच समन्वय बनाये।



समापन , शपथ एवं धन्यवाद समाप्ति

समयावधि : 30 मिनिट

समापन :-

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के प्रशिक्षण के पश्चात् सहयोगकर्ता समापन के समय अपने सम्बोधन में बैठक में आये हुए सभी सदस्यों से यह अपेक्षा व्यक्त करेंगे की एक दिवसीय बैठक में हमारे द्वारा बताई गई सभी जानकारीयों को पूर्ण रूप से समझाकर पूर्ण निष्ठा के साथ अपने ग्राम में अपनाकर अपने गांव को एक बाल मित्र गांव बनाएं जैसे-

- आप सभी अपने गांव के सभी बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, उचित देखभाल करेंगे।
- आप सभी ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति के कर्तव्यों को पूरा करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
- बच्चों के साथ होने वाली किसी अप्रिय घटना को ग्राम स्तरीय संरक्षण समिति को अवगत करें।
- बच्चों की सम्पूर्ण संरक्षण का ध्यान रखें।
- आप सभी हर माह होने वाली बाल सुरक्षा समिति की मासिक बैठक में भाग लेंगे।
- आप सभी अपने व आस पास के सभी बच्चों को नियमित रूप से खुल भेजें।

शपथ :-

ग्राम स्तरीय बाल सुरक्षा समिति के प्रशिक्षण में आये हुए सभी सम्भागियों को सहयोगकर्ता एक जगह एकत्रित कर एक गोले में (गोलाकार) खड़ा कर हर एक सदस्य के द्वारा रस्सी में गाठे लगवाते हुए वह सदस्य एक शपथ लेगा।

हर सदस्य को एक - एक शपथ दिलवाएगा की हम सभी यह शपथ लेते हैं की हम अपने गाव को बाल श्रम से मुक्त, बच्चों को शिक्षा व स्कूल से जोड़ना, बच्चों के लायन में कमी, बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक करना, बाल विवाह से मुक्त करना और अपने गांव को आदर्श एवं बाल सुरक्षित गांव बनाने की शपथ लेते हैं।

उसके बाद सभी सदस्यों से एक-एक कर के शपथ दिलवाएंगे।





**ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण कार्य योजना प्रारूप -
विशेष देवखमाल एंव संरक्षण की श्रेणी में आने वाले बच्चों की समेकित जानकारी**

क्र.स.	श्रेणी	कुल बच्चे	निर्णय लिया गया	जिम्मेदार व्यक्ति	फॉलो किया गया	विशेष टिप्पणी
1	अनाथ बच्चे					
2	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (विकलांग बच्चे)					
3	परित्यक्त बच्चे					
4	जिनके मात-पिता आजीवन कारावास में हो या सजा ए मौत सुनायी गयी हो।					
5	नाता जाने वाली माता के बच्चे					
6	बाल मजदूरी करने वाले बच्चे					
7	बाल विवाहित बच्चे					
8	गुमशुदा बच्चे					
9	पालायन करने वाले बच्चे					
10	विधवा माता के बच्चे					
11	अन्य श्रेणी (यदि हो तो उल्लेखित करें)					

क्र.स.	श्रेणी	पात्र लाभार्थीयों की संख्या	निर्णय लिया गया	जिम्मेदार व्यक्ति	फॉलो किया गया	विशेष टिप्पणी
1	पालनहार					
2	विधवा पैशन					
3	वृद्धा पैशन					
4	निशक्त पैशन					
5	विधवा पुत्री विवाह अनुदान योजना					
6	कस्तुरबा गांधी बालिका आवासिय विद्यालय योजना					
7	डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्राजित विवाह योजना					
8	सहयोग योजना					
9	उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना					
10	आस्था योजना					
11	मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना					
12	पन्नाधाय जीवन अमृत योजना					
13	निशक्त विवाह अनुदान योजना					
14	अनुप्रति योजना					



धन्यवाद :-



अंत में सहयोगकर्ता ग्राम स्तरीय बाल सुरक्षा समिति में आये हुए सभी सम्भागियों को हाथ मिलाकर व नमस्ते कहकर और बैठक में आने के लिए धन्यवाद देंगे और बैठक समाप्त करेगा।



વાગ્ધારા

મુખ્ય કાર્યાલય : સુકામ પોર્ટ કુપડા, બાંસવાડા, રાજસ્થાન પિન કોડ : 327001
ફોન : +91-9414082643 ફોક્સ : +91-9024573411 ઈ-મેલ : vaagdhara@gmail.com
વૈબસાઇટ : www.vaagdhara.org